DreamFolks
Your Airport Experience Amplified !

Dreamfolks Services Ltd.
#501, Tower-2, Fifth Floor, Worldmark
Sector-65, Gurugram – 122018
Haryana, India | 0124-4037306
www.dreamfolks.in | info@dreamfolks.in
CIN : L51909DL2008PLC177181

February 08, 2025

To, The Secretary, Listing Department BSE Limited P. J. Towers, Dalal Street Mumbai – 400001 **Scrip Code:** 543591	To, The Listing Manager, Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051 **Symbol:** DREAMFOLKS

Subject: Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended

Dear Sir(s)/ Madam(s),

Please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisements relating to Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on December 31, 2024. The advertisements were published on February 08, 2025 in editions of Jansatta (Hindi) and Financial Express (English) newspapers. The said Results were approved at the Meeting of the Board of Directors of the Company held on February 07, 2025.

The advertisements can also be accessed at the website of the Company at www.dreamfolks.com.

You are hereby requested to take the above intimation on record.

Thanking you!

Yours faithfully
For Dreamfolks Services Limited

HARSHIT GUPTA
Digitally signed by HARSHIT GUPTA
Date: 2025.02.08 13:58:03 +05'30'

Harshit Gupta
Company Secretary and Compliance Officer

Encl: As above

हाई कोर्ट ने 249 अवैध धार्मिक ढांचों के सर्वेक्षण का दिया निर्देश

पीठ ने धार्मिक समिति को ढांचों की पूरी जानकारी एकत्र करने को कहा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 फरवरी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को शहर भर में सार्वजनिक भूमि पर निर्मित 249 अनधिकृत धार्मिक ढांचों की मौजूदगी पर एक व्यापक सर्वेक्षण और उसके बाद रिपोर्ट के लिए निर्देश जारी किया।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि सूचना एकत्र करने के बाद दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (गृह) या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी छह सप्ताह के भीतर अदालत में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट से भेजा गया था और सार्वजनिक भूमि से अवैध धार्मिक ढांचों को हटाने से संबंधित था। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के वकील ने कहा कि उसने 127 अवैध धार्मिक ढांचों की पहचान की और उन्हें ध्वस्त कर दिया, जिनमें से कुछ संजय वन और जहांपनाह सिटी फारेस्ट में बनाए गए थे। डीडीए ने अदालत को बताया कि 127 संरचनाओं में से 82 की पहचान वन विभाग ने की थी।

डीडीए ने अदालत को बताया कि 127 संरचनाओं में से 82 की पहचान वन विभाग ने की थी।

पीठ ने कहा कि धार्मिक समिति का नेतृत्व दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (गृह) करते हैं। तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि धार्मिक समिति उन 249 मामलों की पूरी जानकारी एकत्र करे जिनकी पहचान अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाने के लिए की गई है। ये जानकारी उन एजंसियों से एकत्र की जाए जिनकी भूमि पर ऐसी संरचनाएं मौजूद हैं और उन एजंसियों से भी जो ऐसी अनधिकृत संरचनाओं को हटाने के लिए जिम्मेदार हैं। अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 14 मई को निर्धारित की। धार्मिक समिति ने कहा है कि उसने अब तक 51 बैठकें की हैं और अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाने के लिए 249 मामलों की सिफारिश की है। अदालत ने कहा कि ये संरचनाएं नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, डीडीए, दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली नगर निगम और रेल मंत्रालय, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली सरकार के कई अन्य विभागों की भूमि पर थीं।

अदालत ने कहा कि एजंसियों ने कार्रवाई धार्मिक समिति के फैसले के अनुसरण में की। वर्ष 2009 में, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक पार्क और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक संरचनाओं के नाम पर कोई अनधिकृत निर्माण नहीं किया जाना चाहिए या इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और राज्य सरकारों को ऐसे मौजूदा ढांचों की समीक्षा करने और उचित कदम उठाने का निर्देश दिया था। वर्ष 2018 में, इसने मामले को उच्च न्यायालयों को भेज दिया था।

सेंट स्टीफेंस कालेज समेत स्कूलों में बम की सूचना निकली फर्जी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 फरवरी।

दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कालेज और दिल्ली-एनसीआर के दो स्कूलों को शुक्रवार को बम की धमकी वाला ई-मेल मिला, जिसके बाद पुलिस ने परिसर की तलाशी के लिए बम निरोधक इकाइयों और श्वान दस्तों को तैनात किया। धमकी भरे ई-मेल दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कालेज, मयूर विहार के एल्कान इंटरनेशनल स्कूल और नोएडा के शिव नादर स्कूल को भेजे गए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बाद में दोनों परिसरों की गहन तलाशी ली और धमकियों को फर्जी करार दिया।

उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त राजा बांठिया ने शुक्रवार को बताया कि सेंट स्टीफेंस कालेज में शुक्रवार सुबह करीब 7:42 बजे बम होने की सूचना मिली थी। इसके बाद मौके पर बम निरोधक दस्ता, श्वान दस्ता, एंबुलेंस व अन्य एजंसियां पहुंच गई। सुरक्षाकर्मियों की मदद से कालेज के हर हिस्से की तलाशी ली गई। पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद सभी ने राहत की सांस ली।

वहीं, अभिषेक धानिया ने बताया कि मयूर विहार में स्थित विद्यालय प्रशासन की ओर से सुबह करीब 6:40 बजे काल कर पुलिस को दी गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने पांडव नगर थाना प्रभारी को काल कर बम की धमकी भरा ई-मेल मिलने के बारे में बताया। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी। घंटों की तलाशी के बाद भी विद्यालय में कोई भी संदिग्ध या बम से संबंधित चीज नहीं मिली। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

पुलिस उपायुक्त (नोएडा) सिंह ने बताया कि पुलिस को शिव नादर स्कूल से बम की धमकी के बारे में सूचना मिली थी। श्वान दस्ता, बम निरोधक इकाइयां, दमकल अधिकारी और पुलिस की टीम परिसर में पहुंचीं और जांच की। लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यह एक फर्जी ई-मेल था, संभवतः किसी छात्र ने भेजा हो।

प्रधानाचार्य अंजू सोनी ने छात्रों के माता-पिता और अभिभावकों को भेजे गए संदेश में कहा कि स्कूल शुक्रवार को तलाशी के लिए बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि आपके साथ यह जानकारी साझा करना चाहते हैं कि हमें स्कूल परिसर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर धमकी मिली है। इसलिए, सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम तलाशी अभियान पूरा करने के उद्देश्य से पूरे दिन के लिए स्कूल बंद कर रहे हैं।

मयूर विहार के एल्कान इंटरनेशनल स्कूल में बम की धमकी के बाद जांच करती पुलिस।

पुलिस उपायुक्त (नोएडा) ने बताया कि पुलिस को शिव नादर स्कूल से बम की धमकी के बारे में सूचना मिली थी। श्वान दस्ता, बम निरोधक इकाइयां, दमकल अधिकारी और पुलिस की टीम परिसर में पहुंचीं और जांच की। लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

खबर कोना

मेट्रो की 'रेड लाइन' पर सेवाएं कुछ देर के लिए रहीं प्रभावित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली,7 फरवरी।

दिल्ली मेट्रो रेल की रिठाला से शहीद स्थल बस अड्डे के बीच चलने वाली रेड लाइन पर नेताजी सुभाष प्लेस और तीस हजारी स्टेशन के बीच शुक्रवार को सेवाएं कुछ देर के लिए विलंबित रहीं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी। सुबह दफ्तर या काम की जगह जाने के व्यस्ततम समय में हुई इस देरी से मेट्रो यात्री परेशान हुए । हालांकि कुछ देर बाद ही सेवाएं सामान्य हो गईं। डीएमआरसी ने सोशल मीडिया मंच ह्एक्सह्न पर एक पोस्ट में कहा कि नेताजी सुभाष प्लेस और तीस हजारी स्टेशन के बीच सेवाओं में देरी हुई। डीएमआरसी ने सुबह नौ बजकर 45 मिनट पर जारी अपने पोस्ट में कहा कि असुविधा के लिए खेद है।

रेजिडेंट चिकित्सकों को साप्ताहिक व आकस्मिक अवकाश देने की मांग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 फरवरी

यूनाइटेड डाक्टर्स फ्रंट(यूडीएफ) ने रेजिडेंट डाक्टरों को नियमानुसार साप्ताहिक और आकस्मिक अवकाश देने की मांग की है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्य मित्तल ने कहा है कि कई मेडिकल कालेजों में पीजी मेडिकल छात्रों को नियमानुसार अवकाश नहीं दिया जाता। इसके कारण छात्रों को मानसिक यातना से गुजरना पड़ता है। मित्तल ने देश के सभी मेडिकल कालेजों में ड्यूटी के आठ घंटे निर्धारित करते हुए इससे ज्यादा देर काम के एवज में अतिरिक्त छुट्टी प्रदान करने की मांग की है।

सांसद इंजीनियर राशिद की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 फरवरी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में मुकदमे का सामना कर रहे जेल में बंद सांसद राशिद इंजीनियर की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सांसद ने संसद के मौजूदा सत्र में हिस्सा लेने के लिए अभिरक्षा पैरोल का अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति विकास महाजन ने बारामूला से सांसद तथा राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) की ओर से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनीं और कहा कि फैसला सुरक्षित रखा जाता है।

सज्जन कुमार के खिलाफ सिख दंगे के मामले में फैसला टला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 फरवरी।

दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित हत्या मामले में शुक्रवार को अपना फैसला 12 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को शुक्रवार को फैसला सुनाना था।

जनवरी में अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ बिंदुओं पर विस्तृत दलीलें पेश करने के लिए समय मांगे जाने के बाद अदालत ने फैसला स्थगित कर दिया था। मामला 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान यहां सरस्वती विहार इलाके में दो व्यक्तियों की हत्या से संबंधित है।

12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई।

अदालत ने एक नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से संबंधित मामले में अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस संबंध में शुरू में पंजाबी बाग थाने में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में एक विशेष जांच दल ने जांच का जिम्मा संभाल लिया था। 16 दिसंबर, 2021 को अदालत ने कुमार के विरुद्ध आरोप तय किए और उनके खिलाफ 'प्रथम दृष्टया' मामला सही पाया।

'नए युग' के साइबर अपराधों के खिलाफ जनहित याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 फरवरी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे 'नए युग' के साइबर अपराधों के खिलाफ एक जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने केंद्र को चार सप्ताह का समय दिया और अगली सुनवाई 19 मार्च के लिए तय की। पीठ ने कहा कि भारत संघ द्वारा चार सप्ताह के भीतर हलफनामा, जवाब दाखिल किया जाए। उसके बाद दो सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल किया जाए।

पीठ ने केंद्र को चार सप्ताह का समय दिया और अगली सुनवाई 19 मार्च के लिए तय की।

नोटिस जारी करते हुए उच्च न्यायालय ने 2024 में केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और भारतीय रिजर्व बैंक को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। जनहित याचिका में साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूकता पैदा करने और शिकायत दर्ज करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अक्षय और उर्वशी भाटिया ने कहा कि अब साइबर अपराधी सुप्रीम कोर्ट सहित फर्जी अदालती आदेशों, प्राथमिकी और गिरफ्तारी वारंटों का डर दिखाकर समझौते करने की आड़ में निर्दोष नागरिकों से पैसा वसूली करते हैं। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं में से एक को 'डिजिटल अरेस्ट' के तहत कथित तौर पर दिल्ली की एक अदालत द्वारा जारी किया गया 'जाली और मनगढ़ंत' गिरफ्तारी वारंट मिला।

साइबर धोखाधड़ी कर लोगों को ठगने वाले पांच आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 फरवरी।

दक्षिण-पश्चिम जिला साइबर थाना पुलिस ने चीन की एक कंपनी के लिए काम कर 'साइबर धोखाधड़ी' कर लोगों के साथ ठगी करने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अभिषेक यादव, इमरान कुरैशी, असद कुरैशी, देव सागर और जावेद के रूप में हुई। पुलिस ने इनके पास से 11 मोबाइल, छह एटीएम, कई बैंकों की पास बुक व चेक बुक बरामद की है।

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि हाल ही में उन्होंने सेना से सेवानृवित एक अधिकारी के साथ 15 लाख की ठगी की थी।

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि हाल ही में उन्होंने सेना से सेवानृमित एक अधिकारी के साथ 15 लाख की ठगी की थी। पुलिस को पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि आरोपी चीन की मध्यप्रदेश के झांसी स्थित कंपनी के लिए काम करते हैं।

जिला पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने शुक्रवार को बताया कि बीते आठ दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय के एनसीआरपी पोर्टल पर सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी ने साइबर थाने में शिकायत दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें मुंबई की एक अदालत से धनशोधन मामले में गैर-जमानती वारंट जारी होने का फोन आया। इसके बाद उन्हें वाट्सएप वीडियो निगरानी में रखा गया। आरोपी ने उनसे अपनी एक्सिस बैंक खाता से 15 लाख रुपए तुरंत स्थानांतरण करने को कहा, जो उन्हें अगले दिन ब्याज के साथ वापस करने का वादा भी किया गया।

DELHIVERY

DELHIVERY LIMITED

CIN: L63090DL2011PLC221234

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2024

(Rs. in million, unless otherwise stated)

S. No.	Particulars	Quarter ended			Nine months period ended		Year ended
		December 31, 2024	September 30, 2024	December 31, 2023	December 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	23,782.98	21,897.33	21,944.68	67,403.35	60,659.99	81,415.38
2	Net Profit/(Loss) (before tax and exceptional items)	238.10	86.23	311.93	905.44	(1,659.88)	(2,220.38)
3	Net Profit/(Loss) before tax (after exceptional items)	238.10	86.23	234.39	854.10	(1,737.42)	(2,444.48)
4	Net Profit/(Loss) after tax (after exceptional items)	249.88	102.04	117.06	895.53	(1,807.15)	(2,491.86)
5	Total Comprehensive Income/(Loss)	286.75	114.58	133.09	938.42	(1,779.50)	(2,450.02)
6	Equity Share Capital	742.81	740.04	735.04	742.81	735.04	736.79
7	Other Equity						90,709.67
8	Earning/(Loss) per equity share* (Face Value of Re. 1)						
	(a) Basic (In Rs):	0.34	0.14	0.16	1.21	(2.47)	(3.40)
	(b) Diluted (In Rs):	0.33	0.13	0.15	1.18	(2.47)	(3.40)

*Earning/(Loss) per share is not annualized for quarter and nine months period ended.

Notes:

1 Additional information on Standalone financial results: (Rs. in million)

S. No.	Particulars	Quarter ended			Nine months period ended		Year ended
		December 31, 2024	September 30, 2024	December 31, 2023	December 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	22,042.75	20,199.63	20,268.51	62,303.97	55,753.11	74,540.82
2	Net Profit/(Loss) before tax	380.09	190.85	529.74	1,290.70	(716.83)	(1,679.68)
3	Net Profit/(Loss) after tax	380.09	190.85	529.74	1,290.70	(716.83)	(1,679.68)

2 The above results are an extract of the detailed format of financial results for the quarter ended December 31, 2024 which are also available on the BSE Limited website (www.bseindia.com), the National Stock Exchange of India Limited website (www.nseindia.com) and on the Company's website (https://www.delhivery.com/company/investor-relations).

3 The above financial results has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" ("Ind AS 34"), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("the Regulations").

4 The above results as reviewed by the Audit Committee, have been approved by Board of Directors at its meeting held on February 07, 2025.

For and on behalf of the Board of Directors of Delhivery Limited
Sd/-
Sahil Barua
Managing Director and Chief Executive Officer
DIN : 05131571

Date: February 7, 2025
Place: Goa

Regd. Office: N24-N34, S24-S34, Air Cargo Logistics Centre-II, Opposite Gate 6 Cargo Terminal, IGI Airport, New Delhi 110037 IN
E-mail: corporateaffairs@delhivery.com; **Website:** www.delhivery.com

DreamFolks
Your Airport Experience Amplified !

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON DECEMBER 31, 2024

The Board of Directors of the Company, at the meeting held on February 07, 2025, approved the unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on December 31, 2024 ("**Financial Results**").

The Financial Results along with the Limited Review Report, have been posted on the Company's website at https://www.dreamfolks.com/results-and-reports.html and can be accessed by scanning the QR Code.

Note: The above intimation is in accordance with Regulation 47(1) read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

For and on behalf of the Board
Dreamfolks Services Limited
Sd/-
Chairperson and Managing Director
DIN: 06849062

Place: Gurugram
Date: February 07, 2025

Dreamfolks Services Limited, Regd. Office: 26, DDA Flats, Panchsheel Park, Shivalik Road, New Delhi – 110017
Tel.: 0124-4037306, **Email:** investor.support@dreamfolks.in, **Website:** www.dreamfolks.com, **Corporate Identity No. (CIN):** L51909DL2008PLC177181

Lounge Access | Meet & Assist | Spa Services | F&B Offerings | Airport Transfers | Transit Hotels | Golf | VISA Services | eSIM

REVISED INDUSTRIAL POLICY FOR 2025-2030

Karnataka to offer 10% extra incentive for manufacturing

ANEES HUSSAIN
Bengaluru, February 7

THE KARNATAKA GOVERNMENT will offer an additional 10% incentive to companies that transition their research and development (R&D) operations into local manufacturing units. This initiative is part of the state's upcoming industrial policy for 2025-2030, aimed at boosting domestic production, MB Patil, minister for large and medium industries and infrastructure development, told *FE*.

"Of the Fortune 500 companies, over 400 have R&D centers in Bengaluru, including Samsung, Airbus, Boeing and Mercedes-Benz. However, only about 10% of their manufacturing happens here. The new incentive structure should encourage more companies to establish manufacturing units locally," Patil said.

The revised industrial policy will introduce flexible incentives, allowing businesses to opt between production-linked or capital-based benefits. It will also introduce employment-based incentives, with additional advantages for companies hiring women.

Furthermore, the state will allocate ₹5,000 crore to enhance infrastructure, ensuring water supply to industrial parks and offering land parcels on a lease basis. Companies will also have the option to generate their own power needs within industrial zones.

"We are offering firms the opportunity to invest 26% in solar or wind energy projects," Patil added. Karnataka currently derives 65% of its installed power capacity from renewable sources.

To streamline business processes, Karnataka is collaborating with Microsoft to launch an AI-driven single-window portal. This platform is expected to cut application processing time from 100 days to 50 and will integrate key information on regulations, land availability, and application tracking in a mobile-friendly format.

The state is also promoting industrial growth beyond Bengaluru. Belgaum is being positioned as a hub for electronic manufacturing, aerospace, and FMCG parks, while Bijapur will cater to water-intensive industries like semiconductors.

Mysore, Hubli, and Belgaum will be developed as new IT and startup hubs, with reduced land prices and added incentives.

These initiatives come ahead of Invest Karnataka 2025, scheduled to begin on February 12. The government has set a ₹10 lakh crore investment target, expecting a 70% conversion rate.

FUTURE PROSPECTS

- New policy to provide flexible incentives, allowing firms to choose between production-linked and capital-based benefits
- State govt is developing Belgaum as a hub for electronic manufacturing, aerospace, and FMCG park
- State govt will allocate ₹5,000 crore to enhance infra
- Bijapur will cater to water-intensive industries like semiconductors

MB PATIL, KARNATAKA MINISTER

"Firms such as Samsung, Airbus, Boeing and Mercedes-Benz have R&D centres in Bengaluru. However, only about 10% of their manufacturing happens here"

Cabinet nod likely for ITI upgrade in current fiscal

MANU KAUSHIK
New Delhi, February 7

THE ITI (INDUSTRIAL Training Institute) upgradation scheme, introduced in the Budget 2024-25, is expected to receive Cabinet approval within the current fiscal year, an official in the ministry of skill development told *FE*.

"The ministry has prepared the proposal for the scheme, and it will be sent to the Cabinet shortly. We have held multiple rounds of consultations with various stakeholders, including state governments and industry, to develop a comprehensive plan for upgrading existing ITIs," the official said.

In the recent budget, finance minister Nirmala Sitharaman allocated ₹3,000 crore for the scheme in FY26—three times the ₹1,000 crore approved in the previous Budget for FY25. However, the ministry has spent only ₹294 crore in FY25 on preparatory work.

Although the scheme was originally scheduled for launch in January, it is still awaiting final approval from the minister for skill development. "The proposal is yet to be cleared by the minister, but we expect the scheme to kick off within the current fiscal," the official added.

The department of expenditure has permitted the ministry to spend up to ₹10 crore on preparatory activities, and the revised estimate for the scheme has been updated to ₹294 crore.

Experts caution that upgrading ITIs is a complex challenge, as similar efforts in the past have failed to deliver the desired outcomes. In response to a query from the Standing Committee, the ministry acknowledged that "the financial assistance provided under various schemes in the past was suboptimal to cover the entire upgradation needs of ITIs, particularly given the growing investment requirements for infrastructure upkeep, capacity expansion, and the introduction of capital-intensive new-age trades."

However, the ministry asserts that the new upgradation scheme will be different, adopting a challenge-based selection process for ITIs while ensuring state participation, industry collaboration, and an outcome-driven implementation strategy—key distinctions from previous initiatives.

LOOKING AHEAD

- Govt has allocated ₹3,000 cr for ITI upgradation scheme in FY26
- It was ₹1,000 cr in the previous Budget
- Only ₹294 cr was spent in FY25 on preparatory work
- As on Aug 2024, there were 15,034 ITIs functioning
- 3,298 ITIs were government-run

UPWARD TREND

(in $ billion)

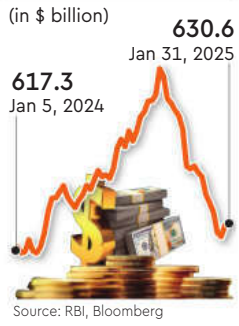

Source: RBI, Bloomberg

Forex reserves rise for second week in a row

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, February 7

INDIA'S FOREX RESERVES rose $1.05 billion to $630.607 billion for the week ended January 31, the RBI said on Friday.

In the previous reporting week, the overall reserves had increased by $5.574 billion to $629.557 billion.

This is the second consecutive week of an increase in the reserves, which have otherwise been on a declining trend for the last few weeks due to revaluation along with forex market interventions by RBI to help reduce volatilities in the rupee.

The forex reserves had increased to an all-time high of $704.885 billion in end-September 2024.

For the week ended January 31, foreign currency assets, a major component of the reserves, decreased by $207 million to $537.684 billion, the data released on Friday showed.

Gold reserves increased by $1.242 billion to $70.893 billion during the week, the central bank said.

LIC profit rises 16% in third quarter

NARAYANAN V
Chennai, February 7

LIFE INSURANCE CORPORATION of India (LIC) on Friday reported a 16% year-on-year (y-o-y) increase in consolidated net profit for the December quarter (Q3FY25), reaching ₹11,009 crore. The state-run insurer's profit also surged 42% sequentially from ₹7,729 crore in Q2FY25.

Consolidated net premium income for Q3FY25 stood at ₹1.07 lakh crore, marking a 9% decline from ₹1.17 lakh crore in the same quarter last year. It was also lower than the ₹1.20 lakh crore reported in Q2FY25.

LIC MD & CEO Siddhartha Mohanty attributed the decline in premiums to Irdai's new surrender value guidelines, which came into effect on October 1, 2024. "The last quarter was a momentous period for the entire industry," he said, acknowledging the guidelines had some impact on premium growth.

He also noted that LIC's agents needed time to adapt to the new product regulations. "But we are confident this quarter will be better than any other quarter," he added. As of 9MFY25, LIC had 1.57 million agents, contributing 96% of its new business premiums.

Mohanty downplayed concerns about the impact of the recent income tax limit hike to ₹12 lakh on LIC's business. "People will now take insurance purely for insurance purposes," he said, emphasising that 72% of tax filers had already migrated to the new tax regime, which has not had a significant effect on the industry.

REPORT CARD (₹ cr) Q3FY24 Q3FY25 % chg

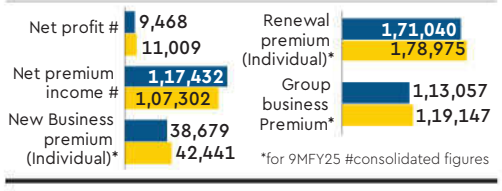

*for 9MFY25 #consolidated figures

CABINET DECISIONS

Govt clears restructuring of Skill India Programme with ₹8,800-crore outlay

THE UNION CABINET has approved the continuation and restructuring of the Skill India Programme until 2026. The restructuring brings together three key skilling initiatives under one umbrella—Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0, Pradhan Mantri National Apprenticeship Promotion Scheme and Jan Shikshan Sansthan scheme. The programme will have a total outlay of ₹8,800 crore over three years, from FY23 to FY26. The flagship schemes have collectively benefitted over 22.7 million individuals to date. **FE BUREAU**

Sanitation workers' commission gets 3-year extension

UNION CABINET APPROVED the extension of the tenure of National Commission for Safai Karamchari for three more years. The total financial implication of f the extension would be approximately ₹50.91 crore. **PTI**

DELHIVERY

DELHIVERY LIMITED

CIN: L63090DL2011PLC221234

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2024

(Rs. in million, unless otherwise stated)

S. No.	Particulars	Quarter ended			Nine months period ended		Year ended
		December 31, 2024	September 30, 2024	December 31, 2023	December 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	23,782.98	21,897.33	21,944.68	67,403.35	60,659.99	81,415.38
2	Net Profit/(Loss) (before tax and exceptional items)	238.10	86.23	311.93	905.44	(1,659.88)	(2,220.38)
3	Net Profit/(Loss) before tax (after exceptional items)	238.10	86.23	234.39	854.10	(1,737.42)	(2,444.48)
4	Net Profit/(Loss) after tax (after exceptional items)	249.88	102.04	117.06	895.53	(1,807.15)	(2,491.86)
5	Total Comprehensive Income/(Loss)	286.75	114.58	133.09	938.42	(1,779.50)	(2,450.02)
6	Equity Share Capital	742.81	740.04	735.04	742.81	735.04	736.79
7	Other Equity						90,709.67
8	Earning/(Loss) per equity share* (Face Value of Re. 1)						
	(a) Basic (In Rs):	0.34	0.14	0.16	1.21	(2.47)	(3.40)
	(b) Diluted (In Rs):	0.33	0.13	0.15	1.18	(2.47)	(3.40)

*Earning/(Loss) per share is not annualized for quarter and nine months period ended.

Notes:

1 Additional information on Standalone financial results: (Rs. in million)

S. No.	Particulars	Quarter ended			Nine months period ended		Year ended
		December 31, 2024	September 30, 2024	December 31, 2023	December 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	22,042.75	20,199.63	20,268.51	62,303.97	55,753.11	74,540.82
2	Net Profit/(Loss) before tax	380.09	190.85	529.74	1,290.70	(716.83)	(1,679.68)
3	Net Profit/(Loss) after tax	380.09	190.85	529.74	1,290.70	(716.83)	(1,679.68)

2 The above results are an extract of the detailed format of financial results for the quarter ended December 31, 2024 which are also available on the BSE Limited website (www.bseindia.com), the National Stock Exchange of India Limited website (www.nseindia.com) and on the Company's website (https://www.delhivery.com/company/investor-relations).

3 The above financial results has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" ("Ind AS 34"), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("the Regulations").

4 The above results as reviewed by the Audit Committee, have been approved by Board of Directors at its meeting held on February 07, 2025.

For and on behalf of the Board of Directors of Delhivery Limited
Sd/-
Sahil Barua
Managing Director and Chief Executive Officer
DIN : 05131571

Date: February 7, 2025
Place: Goa

Regd. Office: N24-N34, S24-S34, Air Cargo Logistics Centre-II, Opposite Gate 6 Cargo Terminal, IGI Airport, New Delhi 110037 IN
E-mail: corporateaffairs@delhivery.com; **Website:** www.delhivery.com

DreamFolks
Your Airport Experience Amplified !

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON DECEMBER 31, 2024

The Board of Directors of the Company, at the meeting held on February 07, 2025, approved the unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on December 31, 2024 ("**Financial Results**").

The Financial Results along with the Limited Review Report, have been posted on the Company's website at https://www.dreamfolks.com/results-and-reports.html and can be accessed by scanning the QR Code.

Note: The above intimation is in accordance with Regulation 47(1) read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

For and on behalf of the Board
Dreamfolks Services Limited
Sd/-
Chairperson and Managing Director
DIN: 06849062

Place: Gurugram
Date: February 07, 2025

Dreamfolks Services Limited, Regd. Office: 26, DDA Flats, Panchsheel Park, Shivalik Road, New Delhi – 110017
Tel.: 0124-4037306, **Email:** investor.support@dreamfolks.in, **Website:** www.dreamfolks.com, **Corporate Identity No. (CIN):** L51909DL2008PLC177181

Lounge Access · Meet & Assist · Spa Services · F&B Offerings · Airport Transfers · Transit Hotels · Golf · VISA Services · eSIM

The Shipping Corporation Of India Ltd.

(A Government of India Enterprise)

Navratna Company (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified)

Registered office: Shipping House, 245, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai City, Mumbai, Maharashtra, India, 400021
Tel.: 91-022-2277 2220 • Fax: 91-022-2202 6905
Website: www.shipindia.com • Twitter: @shippingcorp
Email: sci.cs@sci.co.in • CIN: L63030MH1950GOI008033

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024

(Amount in ₹ lakhs)

Sr. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited)
1	Total income from Operations	1,33,714	4,38,590	1,36,286	1,35,013	4,39,980	1,36,302
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	7,301	66,395	14,869	8,373	68,045	15,099
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	7,301	66,395	14,869	8,373	68,045	15,099
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	6,480	64,194	13,205	7,552	65,844	13,435
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	6,547	63,765	14,304	10,689	65,131	12,092
6	Equity Share Capital	46,580	46,580	46,580	46,580	46,580	46,580
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (in ₹)						
	Basic :	1.39	13.78	2.83	1.62	14.14	2.88
	Diluted :	1.39	13.78	2.83	1.62	14.14	2.88

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine Months ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the Quarterly/Nine Months ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites.(**www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**) Company's website : **www.shipindia.com**. The same could also be accessed by scanning the Quick Response (QR) Code provided herein.

b) Standalone & Consolidated Financial results for the Quarter and Nine Months ended 31st December 2024 are in compliance with Indian Accounting Standards (Ind-AS).

c) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 7th February 2025.

Place : Mumbai
Date : 07.02.2025

For The Shipping Corporation of India Ltd
Capt. B.K.Tyagi
Chairman & Managing Director
DIN - 08966904

TRANSPORTING GOODS. TRANSFORMING LIVES.